जनसत्ता

1 जून, 2019

संतुलित आधार

नई सरकार में मंत्रिमंडल के गठन और मंत्रियों के विभागों के बंटवारे का काम लगभग पूरा हो चुका है। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक ही सरकार की तस्वीर में इस बात की खोज की जाएगी कि देश और राजनीतिक सहयोगियों के बीच मौजूद भिन्नताओं के मद्देनजर किस स्तर तक संतुलन बिठाया गया है। इस लिहाज से देखें तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी मौजूदा सरकार ने अपनी ओर से इस बात का ध्यान रखने की कोशिश की है कि सबको अपनी नुमाइंदगी दिखे। इसके बावजूद इतने बड़े देश में सभी पक्षों को चूंकि पूरी तरह संतुष्ट करना संभव नहीं है, इसलिए अगर संतुलन के कुछ सवाल बाकी रहेंगे तो इसमें कोई हैरानी बात नहीं होगी। गौरतलब है कि न केवल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सभी सहयोगियों को उनकी मांग के मुताबिक जगह देना संभव नहीं हुआ, बल्कि पिछली बार खुद राजग सरकार में मंत्री रहे कई ऊंचे कद के नेताओं को भी मौका नहीं मिला। मसलन, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, सुरेश प्रभु, महेश शर्मा, मेनका गांधी जैसे कद्दावर नेता मौजूदा मंत्रिमंडल में नहीं हैं। जाहिर है, यह सवाल चर्चा का केंद्र जरूर रहेगा कि इस बार बाहर रह गए ज्यादातर मंत्रियों के शामिल नहीं होने की वजह उनका प्रदर्शन रहा या नई सरकार में नए चेहरों को जगह देने के लिए कुछ पुराने लोगों को किनारे किया गया। यों अरुण जेटली ने खुद पत्र लिख कर मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं होने की इच्छा जताई थी।

सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह रही कि बिहार में भाजपा की प्रमुख सहयोगी पार्टी जदयू इस बार सरकार या मंत्रिपरिषद से बाहर है। इसका कारण शायद यह है कि सरकार में शामिल होने का प्रस्ताव जदयू को अपने अनुकूल नहीं लगा और इसलिए उसने बाहर रहने का फैसला किया। लंबे समय से भाजपा की अच्छी सहयोगी मानी जाने वाली पार्टी अगर सरकार गठन से संतुष्ट नहीं है तो यह देखने की बात होगी कि आने वाले वक्त में जदयू का क्या रुख रहता है और उसका सत्ता-संतुलन में क्या असर पड़ता है। हालांकि तमिलनाडु में भाजपा की सहयोगी पार्टी अन्नाद्रमुक को भी मंत्रिपरिषद में फिलहाल जगह नहीं मिल सकी। इसके अलावा, चुनाव में सामाजिक समीकरण की बुनियाद पर गठित गठबंधनों का सामना करने के मकसद से राजग और भाजपा ने भी उसी के मुताबिक बिसात बिछाने की पूरी कोशिश की थी। यही वजह है कि नतीजे के आकलन में जातिगत समीकरणों का मुद्दा प्रमुख रहा और इसकी छाया सरकार के गठन में साफतौर पर देखी जा सकती है। कुल अट्ठावन मंत्रियों में अगड़ी जातियों का प्रभाव साफ दिखता है, लेकिन अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति और जनजातियों को भी पर्याप्त जगह मिली है।

जहां तक महिलाओं की नुमाइंदगी का सवाल है, पिछली राजग सरकार में मंत्रिपरिषद में दस महिलाओं को शामिल किया गया था, जबकि इस बार केवल छह महिलाओं को जगह मिल सकी। इसके बावजूद कहा जा सकता है कि नई सरकार के गठन में इस बात का खयाल रखने की कोशिश की गई है कि समाज के सभी वर्गों को अपना प्रतिनिधित्व दिखे। फिर भी उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा प्रतिनिधि और दक्षिण भारत में खासी सीटें मिलने के बावजूद वहां से कुल चार चेहरों की उपस्थिति और खासतौर पर तमिलनाडु से एक भी मंत्री का नहीं होना सत्ता में संतुलन के आकलन का आधार बनेगा। हालांकि विभागों के बंटवारे के मामले में इस बात की पूरी कोशिश की गई है कि देश भर में इसका सकारात्मक संदेश जाए। अब यह देखने की बात होगी कि इस समूची कवायद के बाद आने वाले वक्त में सरकार क्षेत्रीय सहित दूसरे तमाम पक्षों के साथ संतुलन कायम करने में कितनी कामयाब हो पाती है!

खतरे का संदेश

हर साल इकतीस मई को मनाया जाने वाला विश्व तंबाकू निषेध दिवस इस बात का संदेश देकर जाता है कि अब हम तंबाकू के सेवन को बंद करें और आने वाली पीढ़ियों को गंभीर संकट से बचा लें। लेकिन लगता है यह संदेश मात्र इस दिन विशेष के लिए होता है, अगले दिन से हम सब इसे भुला देते हैं। इसी का नतीजा है कि आज सिर्फ भारत में नहीं, ज्यादातर विकासशील देशों में बच्चों से लेकर उम्रदराज लोग तक तंबाकू के नशे के आदी हैं। मादक पदार्थों में अगर किसी पदार्थ का सबसे ज्यादा सेवन किया जाता है तो वह तंबाकू है। बीड़ी, सिगरेट, पान, गुटखा जैसे तमाम रूपों में तंबाकू का नशा सामान्य है। चूंकि तंबाकू से बने उत्पाद सस्ते और आसानी से उपलब्ध होते हैं, इसलिए किसी और नशीले पदार्थ के मुकाबले तंबाकू का नशा करने वालों का वर्ग कहीं ज्यादा बड़ा है। हालांकि सब जानते हैं कि तंबाकू एक नहीं, कई गंभीर और जानलेवा बीमारियों का कारण बन सकता है, फिर भी इसे छोड़ नहीं पाते। ऐसे में सवाल उठता है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस का आखिर औचित्य क्या रह जाता है। सवाल है कि इसके जानलेवा होने के बारे में जानते हुए भी इस मसले पर समाज जागरूक क्यों नहीं हो पा रहा? क्या यह सरकार और समाज के लिए चिंता और विचार का विषय नहीं होना चाहिए?

इस बार विश्व तंबाकू निषेध की थीम 'तंबाकू और फेफड़े का स्वास्थ्य' रखी गई है। जाहिर है, पूरी दुनिया में लोगों को यह बताने की कोशिश हो रही है कि तंबाकू फेफड़ों के लिए कितना हानिकारक है, बीड़ी-सिगरेट का धुआं कितनी तेजी से फेफड़ों को कमजोर खत्म करता हुआ न जाने कितनी गंभीर बीमारियों से ग्रस्त कर सकता है। वैसे ही भारत में वायु प्रदूषण लोगों के स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। लाखों लोग जहरीली हवा से होने वाली बीमारियों से मर रहे हैं। ऐसे में तंबाकू का सेवन करने वालों के लिए तो खतरा कहीं ज्यादा बड़ा और गंभीर है। तंबाकू का सेवन करने से पच्चीसों बीमारियां और चालीस से ज्यादा तरह का कैंसर हो सकता है। सरकारी आंकड़ों की मानें तो भारत में धूम्रपान करने वालों की संख्या बारह करोड़ है। लेकिन यह आंकड़ा हकीकत से कोसों दूर ही होगा। गांवों, कस्बों, शहरों से लेकर महानगरों तक में शायद ही कोई ऐसी दुकान, थड़ी, गुमटी होगी जहां बीड़ी, सिगरेट और गुटखा न मिलता हो। अधिसंख्य आबादी के लिए तंबाकू के उत्पाद रोजमर्रा की लत बन चुके हैं। इसीलिए तंबाकू के खतरों के बारे में लोगों को जागरूक करना सरकारी तंत्र के लिए एक असंभव-सा काम बन गया है।

ऐसे में बात घूम फिर कर जागरूकता पर आ जाती है। हालांकि जागरूकता अभियान चलते भी हैं, लेकिन हमारे यहां वे दिखावटी ज्यादा होते हैं। दूसरी ओर, कई विकसित देशों के उदाहरण सामने हैं जहां तंबाकू के इस्तेमाल के खिलाफ सरकार की पहल से बड़े जागरूकता अभियान चले और इनका परिणाम यह रहा कि धूम्रपान करने वालों की संख्या में खासी कमी देखी गई। लेकिन भारत में ऐसे प्रयास नहीं दिखते। इसके पीछे बड़ा कारण तंबाकू उद्योग के हित हैं, सरकार इसे खत्म नहीं होने देना चाहती। तंबाकू के उपभोग के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। तंबाकू की बड़े पैमाने पर खेती होती है। तंबाकू की खेती और इससे जुड़े उद्योग में तीन करोड़ लोग लगे हैं। सरकार को खरबों रुपए का राजस्व मिलता है। ऐसे में क्या सरकारी तंत्र से उम्मीद की जा सकती है कि वह देश को तंबाकू मुक्त बनाएगा?

कल्पमेधा

प्रजातंत्र का अर्थ मैं समझता हूं कि उसमें नीचे से नीचे और ऊंचे से ऊंचे आदमी को आगे बढ़ने का समान अवसर मिले।

–महात्मा गांधी

क्यों न लगे ई-सिगरेट पर पाबंदी

सौरभ जैन

अब तक दुनिया के छत्तीस देशों, जिनमें मॉरीशस, आस्ट्रेलिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, थाईलैंड, ब्राजील, मेक्सिको, उरुग्वे, बहरीन, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात तथा भारत के बारह राज्य शामिल हैं, में ई-सिगरेट की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। लेकिन भारत के अधिकांश राज्यों में यह अब भी कई रूपों में उपलब्ध है।

हाल में वाणिज्य मंत्रालय ने कानून मंत्रालय से ई-सिगरेट बनाने और इसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाने की मांग की है। वाणिज्य मंत्रालय के मतानुसार कानून की आवश्यकता इसलिए है कि इसके अभाव में ई-सिगरेट के आयात पर प्रतिबंध लगाना पूरी तरह संभव नहीं है। यदि बगैर वैधानिक उपायों के ई-सिगरेट के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया तो यह वैश्विक व्यापार के मानदंडों के विपरीत होगा। इससे पहले भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम के आयात पर रोक लगाने के लिए एक अधिसूचना जारी करने की मांग वाणिज्य मंत्रालय से की थी। इस मांग में ई-सिगरेट के साथ फ्लेवर्ड हुक्का नामक मादक पदार्थ भी शामिल था। हालांकि इसकी रोकथाम की कवायद तभी से प्रारंभ हो गई थी जब पिछले साल अगस्त में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम के विनिर्माण, बिक्री एवं आयात रोकने के लिए एक परामर्श जारी किया था। ऐसा करने के लिए आधार दिल्ली उच्च न्यायालय की मानव स्वास्थ्य को लेकर चिंता थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने ई-सिगरेट के खतरों की रोकथाम में हो रही देरी पर गहरी चिंता व्यक्त की। नतीजतन, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सभी दवा नियंत्रकों को अपने अधिकार क्षेत्र में ई-सिगरेट और फ्लेवर्ड हुक्का सहित इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम के विनिर्माण, बिक्री, आयात और विज्ञापन की अनुमति नहीं देने का निर्देश दिया था। ई-सिगरेट मानव स्वास्थ्य के लिए इतनी हानिकारक है कि इस साल अप्रैल में भारत के चौबीस राज्यों और तीन केंद्रशासित प्रदेशों के एक हजार से अधिक डाक्टरों ने भारतीयों, विशेषकर युवाओं में इसकी लत लगने के पूर्व इस पर प्रतिबंध लगा देने की मांग की है।

ई-सिगरेट एक बैटरी संचालित यंत्र है जो तरल निकोटीन, प्रोपलीन, ग्लाइकॉल, पानी, ग्लिसरीन के मिश्रण को गर्म करके एक एअरोसोल बनाता है जो असली सिगरेट का अनुभव प्रदान करने का कार्य करता है। ई-सिगरेट की बिक्री सर्वप्रथम 2004 में चीन के बाजारों में तंबाकू के विकल्प के रूप में प्रारंभ की गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2005 से ई-सिगरेट के व्यवसाय को वैश्विक व्यापार बनने की बात को स्वीकार करता है। वर्तमान में तो यह व्यवसाय लगभग तीन अरब डॉलर तक पहुंच गया है। जाहिर है, इसकी प्रवृत्ति धूम्रपान के आदी व्यक्तियों में तेजी से बढ़ रही है। धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों में ई-सिगरेट के प्रति आकर्षण बढ़ने का कारण इसका दुष्प्रचार है। सिगरेट सेवन करने वालों के मध्य इस भ्रांति को फैलाया गया है कि ई-सिगरेट के सेवन से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि अब तक सिगरेट का सेवन करने वाले लोग इस बात से वाकिफ थे कि सिगरेट से कैंसर, फेफड़ों से संबंधी रोग, श्वसन तंत्र पर बुरा प्रभाव जैसी समस्याएं होती हैं। सिगरेट में पाए जाने वाले निकोटीन का प्रभाव सिगरेट पीने के चालीस मिनट बाद भी रहता है। इसलिए इस भ्रांति को फैलाया गया गया कि सिगरेट की तुलना में ई-सिगरेट हानिरहित है। इस भ्रांति ने ई-सिगरेट के व्यवसाय को वैश्विक रूप से समृद्ध बना दिया और अपने दैनिक जीवन में धूम्रपान को जीवन शैली का हिस्सा बना चुके लोग स्वतः इस ओर आकर्षित होते चले गए।

ई-सिगरेट के प्रचलन में आने के बाद धूम्रपान करने वालों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। निरंतर ई-सिगरेट का सेवन करने वालों की संख्या में वृद्धि होते देख ब्रिटेन की स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाली संस्था एक्शन ऑन स्मोकिंग एंड हेल्थ (ऐश) ने इसके कारणों को जानने के लिए सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण में धूम्रपान करने वाले बारह हजार वयस्कों को शामिल किया गया। अध्ययन से पता चला कि ई-सिगरेट का सेवन वाले अधिकांश लोग धूम्रपान कम करने के लिए ई-सिगरेट का सहारा ले रहे हैं। सर्वे में पता चला कि ई-सिगरेट का सेवन करने वाले ऐसे लोगों की संख्या मात्र एक प्रतिशत है, जिन्होंने कभी धूम्रपान नहीं किया। नियमित रूप से सिगरेट का सेवन करने वाले लोगों में ई-सिगरेट का उपयोग करने वालों की संख्या वर्ष 2010 में 2.70 फीसद थी, जो वर्ष 2014 में 17.70 फीसद तक पहुंच गई। जब धूम्रपान छोड़ चुके लोगों से ई-सिगरेट का उपयोग करने का कारण पूछा गया तो इकहत्तर प्रतिशत लोगों ने बताया कि वे धूम्रपान छोड़ने में ई-सिगरेट का सहारा लेना चाहते थे। वहीं दूसरी ओर धूम्रपान करने वाले अड़तालीस प्रतिशत लोगों का

कहना था कि उन्होंने तंबाकू की मात्रा को कम करने के लिए ई-सिगरेट का सहारा लिया। जबकि सैंतीस प्रतिशत लोगों की राय थी कि उन्होंने पैसे बचाने के लिए ई-सिगरेट के विकल्प का चुनाव किया।

भारत में बिकने वाली कुल ई-सिगरेट में से करीब 50 फीसद ई-सिगरेट की बिक्री ऑनलाइन होती है। इसकी आपूर्ति में चीन सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। ऑनलाइन उपलब्धता के चलते बच्चों से लेकर किशोरों तक इसकी पहुंच बहुत आसान हो गई है। ऑनलाइन बाजार जहां जीवनशैली को सुलभ एवं आसान बनाता हैं, वहीं ऐसे उत्पादों की बिक्री के चलते स्वास्थ्य एवं जीवन को संकट में भी ला खड़ा करता है।

ई-सिगरेट के सेवन से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को जानने के लिए किए गए एक अध्ययन में चौंका देने वाले सामने आए। तकरीबन छियानवे हजार लोगों पर किए गए शोध में यह बात सामने आई कि ई-सिगरेट के सेवन से दिल के दौरे का खतरा छप्पन प्रतिशत तक बढ़ जाता है, साथ ही लंबे समय तक इसका सेवन करने से खून के थक्के बनने की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। इतना ही नहीं, ई-सिगरेट की लत के शिकार लोगों में अवसाद का खतरा दुगना हो जाता है। ई-सिगरेट का सबसे अधिक असर गर्भवती महिलाओं, बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य पर होता है। शोध अध्ययन के ये तथ्य उन भ्रांतियों से पर्दा उठाने के लिए काफी हैं जो बताते हैं कि ई-सिगरेट का सेवन हानिरहित है। कुछ समय पूर्व अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च और अन्य सरकारी स्वास्थ्य संगठनों के डाक्टरों को शामिल कर ई-सिगरेट के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभावों के अध्ययन को लिए एक कमेटी बनाई गई थी। उक्त कमेटी ने लगभग ढाई सौ रिपोर्टों का विश्लेषण किया, जिसमें यह नतीजा सामने आया कि ई-सिगरेट से जहर फैल सकता है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इसे बनाने में जिन सामग्रियों का इस्तेमाल होता है वे नुकसानदायक होती हैं और जहरीला प्रभाव पैदा कर सकती हैं।

जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भी इस तरह का शोध किया जा चुका है। जापान में हुए एक शोध के मुताबिक साधारण तंबाकू के मुकाबले ई-सिगरेट में दस गुना अधिक मात्र में कैंसरकारी तत्त्व पाए जाते हैं। इसकी भाप में फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटलडीहाइड जैसे कार्सिनोजेन तत्त्व पाए गए हैं। फॉर्मेल्डिहाइड का इस्तेमाल इमारतों के निर्माण में होता है और ई-सिगरेट में इसकी मात्रा साधारण सिगरेट के मुकाबले ज्यादा पाई गई है। अमेरिकी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने इस बात को स्वीकारा है कि 2011 से 2013 के बीच ई-सिगरेट का इस्तेमाल करने वाले युवाओं की संख्या में तीन गुना वृद्धि दर्ज हुई हैं।

अब तक दुनिया के छत्तीस देशों, जिनमें मॉरीशस, आस्ट्रेलिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, थाईलैंड, ब्राजील, मेक्सिको, उरुग्वे, बहरीन, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात तथा भारत के बारह राज्य शामिल हैं, में ई-सिगरेट की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। लेकिन भारत के अधिकांश राज्यों में यह अब भी कई रूपों में उपलब्ध है। अतः आवश्यक है कि अब ई-सिगरेट पर रोक के लिए शीघ्र कानून का निर्माण किया जाए।

कामयाबी की पगडंडी

संजीव राय

दुनिया मेरे आगे

हमारे परिचय-वृत्त यानी 'सीवी' में हमारी अकादमिक विफलताओं का उल्लेख नहीं होता है, लेकिन प्रिंसटोन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जोहंस हॉउसफेर मनोविज्ञान और लोक मामलों के विद्वान होने के अलावा अपने प्रोफाइल में विफलताओं को दर्ज करने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी असफलता के दस्तावेज को 2016 में ऑनलाइन कर दिया था और देखते-देखते वह लाखों लोगों तक पहुंच गया। उन्होंने खुद प्रिंसटोन विश्वविद्यालय पहुंचने तक की अपनी यात्रा में नौकरी में चयन न होने, छात्रवृत्ति में चयनित न होने, शोध पत्र बिना छपे लौटा दिए जाने और डिग्री-पीएचडी पाठ्यक्रम में नामांकन न होने जैसी असफलताओं का उल्लेख किया है।

अब सीबीएसई और राज्यों के दसवीं और बारहवीं कक्षा के परीक्षा-परिणाम आ चुके हैं। लेकिन वे माता-पिता और बच्चे सामाजिक दबाव झेल रहे होंगे, जिनके नंबर अपेक्षया कम आए होंगे या जो असफल करार दिए गए होंगे। क्या किसी बच्चे की स्कूली परीक्षा में असफलता उसकी खुद की असफलता होती है? क्या इस असफलता में उस स्कूल, उनके अध्यापकों, शिक्षा-व्यवस्था और सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक व्यवस्था की भागीदारी नहीं होती है? शिक्षा शास्त्र और मनोविज्ञान इस बात की वकालत करते हैं कि हर एक बच्चा या व्यक्ति बुनियादी रूप से एक दूसरे से भिन्न होता है। फिर एक जैसी दक्षता विकसित करने और उसे प्रमाण-पत्र जारी करने की पद्धति कहां तक उचित है?

स्कूल समाज का एक छोटा रूप होता है। जैसे समाज में अलग-अलग दक्षता के लोगों की भूमिका होती है, वैसे ही स्कूल में भी अलग-अलग हुनर और प्रतिभा के विद्यार्थी होते हैं। एक अनुमान के मुताबिक सौ विद्यार्थियों की कक्षा में केवल बीस फीसद अकादमिक रूप से बेहतर प्रदर्शन करने वाले होते हैं। अस्सी प्रतिशत विद्यार्थी स्कूल में अकादमिक रूप से औसत होते हैं। लेकिन उनकी रुचि जीवन के विभिन्न आयाम जैसे खेल, संगीत, साहित्य, कला, अन्वेषण, रचनात्मकता आदि में ज्यादा हो सकती है और सार्वजनिक जीवन में वे अपनी पहचान बना लेते हैं। जिन लोगों ने फिल्म या खेल में नाम कमाया है, उनमें से कितनों ने पांच सौ में से चार सौ निन्यानबे अंक हासिल किए हैं? आप अपने आसपास देखिए। स्कूल से बाहर आकर कितनों ने अपनी मेहनत से स्कूल में बनी औसत विद्यार्थी की धारणा को पलट दिया है!

बोर्ड की परीक्षा में जिन विद्यार्थियों के नंबर नब्बे प्रतिशत से अधिक आए, उनमें से कुछ के माता-पिता उनके अंकपत्र फेसबुक पर साझा कर रहे हैं। निश्चित रूप से ऐसे बच्चे प्रशंसा के पात्र हैं। मगर कहीं ऐसा तो नहीं कि जाने-अनजाने मां-बाप अपने बच्चे की उपलब्धियों को अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़ कर देख रहे हैं? परीक्षा में पाए गए नंबरों का उत्सव जीवन के हर मुकाम पर आपको खुशी दे और आप हमेशा अव्वल ही रहें, ऐसा जरूरी नहीं है! सबके जीवन में उतार-चढ़ाव आता रहता है और अगर मां-बाप खुद को देखें तो कितनी बार उन्हें ही असफलता का सामना करना पड़ा है। असफलता का यह अहसास स्कूल-कॉलेज, नौकरी से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक पर होता रहता है। अक्सर स्कूल में जब कोई समूह नृत्य या समूह गायन होता है तो हर अभिभावक की इच्छा होती है कि उनका बच्चा सबसे अगली पंक्ति में हो, तो क्या बीस-तीस में से सभी बच्चे अगली पंक्ति में हो सकते हैं?

दुनिया में होमवर्क को लेकर शिक्षाविदों में एक राय नहीं है। अधिकतर विद्वान इसके बढ़ते बोझ से चिंतित हैं, क्योंकि बच्चों के पास परिवार और सामाजिक मेल-मिलाप के लिए समय नहीं है। जबकि नंबरों की अंधाधुंध दौड़ ने किंडरगार्टन से ही गृहकार्य और कक्षा एक से ट्यूशन की शुरुआत करा दी है। चार-पांच साल के बच्चे दो से तीन घंटे का होमवर्क कर रहे हैं। वह स्कूल अच्छा माना जा रहा है जो तीन-चार साल की उम्र से लिखने की शुरुआत करा दे! जबकि लिखने की शुरुआत छह-सात साल की उम्र से हो तो बेहतर होता है। आज छठी कक्षा से ही बच्चे आइआइटी की कोचिंग करने लगे हैं। बच्चों में प्रथम आने की होड़ और असफल होने पर सामाजिक उपेक्षा का डर उन्हें आत्महत्या की ओर भी उन्मुख कर सकता है। हम अपनी महत्त्वाकांक्षा के नशे में भूल गए हैं कि बच्चे आखिर बच्चे हैं और उन्हें खेलने का भी समय चाहिए। परीक्षा की तैयारी के कारण बहुत सारी बातें स्थगित होती जा रही हैं। बच्चों में बढ़ता तनाव प्रतियोगी परीक्षा का दबाव, अकादमिक सफलता पर जोर अध्यापकों को भी असहज बना रहा है। अध्यापकों पर भी बेहतर परीक्षा परिणाम देने का दबाव स्कूल प्रशासन की ओर से रहता है। तो रास्ता क्या है?

धीरे-धीरे कुछ बच्चे इस भागमभाग वाली शिक्षा-पद्धति से बाहर आ रहे हैं, कुछ परीक्षा के डर से अपराध की ओर भी जा रहे हैं। कुछ सचेत अभिभावक ओपन स्कूल और होम स्कूलिंग को अपना रहे हैं। लेकिन स्कूली सर्टिफिकेट की अनिवार्यता अभी भी स्कूलों की मौजूदगी का आधार है, लेकिन स्कूल में असफलता-सफलता का ठप्पा जीवन में कामयाबी की गरंटी नहीं होता है। केवल अकादमिक दक्षता जीवन में आपको एक बेहतर इंसान नहीं बनाती है। इसलिए प्रोफेसर जोहंस की यह बात तार्किक लगती है कि सफलता का रास्ता असफलताओं की पगडंडी से होकर जाता है।

कांटों का ताज

ऐसा माना जाता है कि पांच साल बाद सरकार का जनाधार कम होने लगता है, पर मोदी के नेतृत्व में भाजपा का जनसमर्थन इसके विपरीत देखने को मिला। जनता ने विपक्ष के तमाम आरोपों और वादों के बाद भी जिस तरह से मोदी सरकार पर अटूट भरोसा जताया है, वह प्रधानमंत्री से आने वाले समय में और बेहतर करने की उम्मीद पाले हुए है। देश को सपनों की इस नाव पर बैठाकर उपलब्धियों की मंजिल तक ले जाना मोदी सरकार के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहने वाला है।

इस बार मोदी सरकार पर भरोसा करने वालों में सबसे पहला स्थान युवाओं का है जबकि हाल ही में एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि बेरोजगारी ने पिछले पैंतालीस सालों के सभी रिकार्ड तोड़ दिए हैं। ऐसे में सरकार के लिए युवाओं के सपने को हकीकत में बदलना सबसे कठिन काम रहेगा। देश की अर्थव्यवस्था हाल-फिलहाल में कोई बेहतर संकेत नहीं दे रही। ऐसे में अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है यह देखने वाला रहेगा। उसने पिछले कार्यकाल में ही किसानों की पीड़ा को समझते हुए उन्हें छह हजार रुपए की सालाना पेंशन देने का ऐलान कर दिया था। लेकिन पेंशन न तो कभी स्थायी समाधान कहा जा सकता है, न ही देश के लिए बेहतर संकेत। ऐसे में संभव है कि सरकार इस बार किसानों की फसल बिक्री को लेकर कोई नई नीति लेकर सामने आए जिससे किसानों की सेहत में सुधार होता दिखाई दे। महिला सुरक्षा पर सरकार पिछले कार्यकाल में कोई बेहतर काम नहीं कर सकी। ऐसे में समझना मुश्किल रहेगा कि सरकार कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए क्या कदम उठाएगी। इस वर्ष निर्भया कांड की पीड़िता के माता-पिता ने वोट देने से भी इंकार कर दिया था क्योंकि उन्हें किसी भी सरकार से कोई उम्मीद नहीं थी। ऐसे में सरकार की महिला सुरक्षा को लेकर जिम्मेदारी और बड़ी हो जाती है।

देश के विकास की बात करें तो सरकार ने गरीबों के लिए सस्ती हवाई यात्रा से लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना तक की शुरुआत की थी। यदि सरकार इस कार्यकाल में देश के हर नागरिक को अपनी छत देने का लक्ष्य हासिल कर लेती है तो यह गरीबी खत्म करने के लिए बड़ा कदम साबित होगा। लेट-लतीफी वाली ट्रेनों को छोड़ कर देश बुलेट ट्रेन में भी बैठने को बेताब है। हालांकि सरकार लगातार इस दिशा में काम रही है। बुलेट ट्रेन आने के बाद भारत भी रफ्तार की दुनिया में चीन और जापान से बराबरी कर लेगा। उम्मीद है कि सरकार इस बार बुलेट ट्रेन पटरी पर दौड़ा कर रहेगी। बहरहाल, वादों की सूची तो और भी लंबी है। पर जनादेश और जनाकांक्षाओं को देख कर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री ने गुरुवार की शाम जो कांटों का ताज पहन लिया है, देखना होगा उसे फूलों का ताज बनाने में वे कितने सफल होते हैं।

● *रोहित यादव, महर्षि दयानंद विवि, रोहतक*

स्वच्छता और स्वास्थ्य

जीवन में स्वास्थ्य का महत्त्व सदियों से बताया जाता रहा है और यह एक व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के विकास के लिए अत्यंत महत्त्व रखता है। इन दिनों स्वच्छता को लेकर राष्ट्रव्यापी अभियान छिड़ा हुआ है और यह खुशी की बात है कि इसका आगाज राजनीतिक क्षेत्र से हुआ है। स्वास्थ्य और स्वच्छता कोई राजनीतिक अवधारणा नहीं हैं। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भी महात्मा गांधी और उनके समर्थक लगातार लोगों को इस दिशा में जागरूक करते रहे। राजनीति शास्त्र की भाषा में स्वच्छता अभियान को न तो वोटों का आधार माना जाता है और न राजनीतिक वैचारिकी। फिर भी यह लोगों के बड़े समूह तक यदि सीधे पहुंच रहा है तो इसे बेहतर पहल ही कहा जाएगा।

● *दिव्यानी त्रिपाठी, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश*

घटती हरियाली

भारत जैसे प्रकृति पूजक देश में पर्यावरण पर गंभीर संकट खड़े हैं और इनसे निपटने में वृक्षारोपण एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जाहिर है, इसका समाधान प्रदूषण कम करने के साथ ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पेड़ लगाने में है। अमूमन होता यह है कि सरकारें या स्वयंसेवी संस्थाएं जोरशोर से बड़े पैमाने पर पौधारोपण तो करती हैं, लेकिन परिणाम लगभग शून्य ही आता है।

पिछले 10-15 वर्षों में यदि ये आयोजन पेड़ों से लगाव पैदा कर नैतिक जिम्मेदारी से किए जाते तो शायद घटती हरियाली का संकट इतना गंभीर नहीं होता। अब ज्यादातर ये आयोजन एक वार्षिक त्योहार की भांति हो गए हैं, जो अपने लोगों को आमंत्रित करने और दूसरे दिन फोटो प्रकाशित होने तक सीमित हो गए हैं। हमारी सभ्यता और संस्कृति में पेड़ों का विशेष महत्त्व रहा है और वे देवतुल्य माने गए हैं। इतिहास में जाकर देखें तो हमें कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं, जहां पौधारोपण का कार्य बहुत हर्षोल्लास और जिम्मेदारी से किया जाता था।

● *सुशील वर्मा, गोरखपुर विश्वविद्यालय*

अस्पतालों का इलाज

जब भी हम भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की चर्चा करते हैं तो अक्सर कई प्रकार के आंकड़ों के साथ मरीजों के समांतर डॉक्टरों और अस्पतालों की कमी का हवाला देते हैं। ऐसे आंकड़ों में अस्पतालों का यांत्रिक अमानवीय व्यवहार ढक जाता है और पूरा ध्यान संसाधनों की कमी पर आ जाता है। संसाधनों की समस्या अपने आप में काफी बड़ी है लेकिन मरीजों के प्रति उपेक्षा का भाव ऐसी समस्या है, जिसे लेकर कभी कहीं भी कुछ नहीं किया जाता। मरीज को यह उपेक्षा पूरे चिकित्सा तंत्र से मिलती है। पूरे चिकित्सा तंत्र का अर्थ है किसी अस्पताल के द्वार पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड से लेकर पर्ची बनाने वाले और डॉक्टर का 'अपॉइंटमेंट' देने वाले, सभी में उपेक्षा का भाव दिखता है।

केवल डॉक्टर अकेला ढांचे को नहीं चलाता। डॉक्टरों के अंदर तो हमदर्दी का भाव होना ही चाहिए। लेकिन जब तक उन्हें सहयोग देने वालों और अन्य कर्मचारियों के अंदर माननीय भाव पैदा नहीं होगा, डॉक्टर चाहे भी तो स्थिति नहीं बदल सकते। मरीज या उसके साथ गए रिश्तेदारों को प्रवेश के साथ ही यह लगना चाहिए कि पूरे अस्पताल की उनके साथ सहानुभूति है और उनका पूरा सहयोग मिल रहा है। हमारे समाज की कई त्रासदियां ऐसी हैं, जो हमदर्दी के अभाव के कारण ही पैदा होती हैं। पर यह स्थिति बदलेगी कैसे? इसके कई तरीके हो सकते हैं। मसलन, स्वास्थ्य महकमे से जुड़े हर व्यक्ति की नियुक्ति के पूर्व प्रशिक्षण की ऐसी व्यवस्था की जा सकती है, जिसमें अस्पताल आने वाले व्यक्ति के बारे में उनकी सोच कैसी हो और उसके प्रति उनका व्यवहार कैसा हो आदि का ज्ञान हो जाए। ऐसा प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाना चाहिए। समय-समय पर 'रिफ्रेशर कोर्स' भी चलते रहने चाहिए। इससे पूरी स्थिति एकदम से बदल जाएगी ऐसा नहीं है, लेकिन एक बड़ा सुधार अवश्य होगा।

● *अजीत कुमार गौतम, उत्तर प्रदेश*

चौपाल

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com